International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

गरीबी एवं गरीबी निवारण कार्यक्रमों का अध्ययन

Abhishekh Rai, (Research scholar), HNBGU,BGR Campus, pauri

Prof. R.S.Negi, Deptt of Economics, HNBGU,BGR Campus, pauri

सारांश

ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति से पता चलता है कि वर्तमान शोध में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के बड़ागाँव विकास खण्ड़ के ग्रामीण विकास पर गरीबी एवं गरीबी निवारण कार्यक्रमों की अभी सीमित एवं दुर्लभ है जिसमें स्वास्थ्य, निरक्षरता खराब सुविधाओं से जुझ रहे ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति दयनीय बनी हुई है। इसके अलावा वित्तीय संसाधनों की कमी उच्च जनसंख्या एवं प्रतिव्यक्ति आय मे कमी से जुझ रहे हैं, वहीं प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। गरीबी भूखमरी एवं बेरोजगारी की समस्या भारत में विकास योजनाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। निर्धनता रेखा की अवधारणओं के मुल मानवीय आवश्यकतायें के अन्तर्गत पूरा करने में असमर्थता के अन्तर्गत से जुड़ी हुई है। जैसे बीमारीयों से बचने की क्षमता, पर्याप्त पौष्टिक आहार प्राप्त होना, रहने के लिए उपयुक्त जगह, पहने के लिए उपयूक्त वस्त्र, कुछ न्यूनतम स्तर तक शिक्षित होना एवं आर्थिक–सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना। परिवार में सदस्यों का अधिक होना, वित्त की समस्या, घर में कोई शिक्षित न होना, स्वयं का अशिक्षित होना, बेरोजगारी, छोटी उम्र में मजदूरी करना, पितृ सम्पत्ति का होना, दुसरों के जमीनों में मजदूरी करना, अस्वस्थता, अत्यधिक ऋण होना, सरकारी योजनाओं की जागरुकता का अभाव सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों से मनरेगा कार्यक्रमों से असन्तुष्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन असन्तुष्ट एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम असन्तुष्ट थे, वहीं इन्दिरा आवास योजना से चयनित परिवारों को सन्तुष्ट थे। कुल नमुना का आकार 400 उत्तरदाताओं का था। आंकड़े के विश्लेषण के लिए एसपीएसएस सांख्यिकीय 23 संस्करण सॉफ्टवेयर कारक विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

संकेत शब्द– गरीबी के कारण एवं पहचान, गरीबी निवारण कार्यक्रमों

❖ परिचय

50 वर्षो से गरीबी भगाओं के सिर्फ नारे लगे, पिछले पांच–छह साल में उठाए गए अहम कदम देश से गरीबी भगाने के लिए लगभग 50 साल से नारे लगाए जाते रहे, लेकिन शायद पिछले पांच छह वर्षो में ही इसके लिए अहम कदम उठाए गए। हाल के इन वर्षों में मूलभूत जरूरते पूरी होने के साथ ही गरीबी

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

उन्मूलन की रफ्तार तेज हुई। गरीबी को लेकर आखिरी आंकड़ा आठ साल पहले वर्ष 2011 में आया था। और उस वक्त यह तकरीबन तीस फीसद थी। माना जा रहा है, कि नया आंकड़ा इस साल जून में आएगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है, कि जिस तरह गरीबी के कारणों की जड़ पर हमला हुआ है उससे गरीबी के आंकड़ें में तेज गिरावट आएगी। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में लोगों को गरीबी से निकालने का समग्र प्रयास पहली बार किया गया है। 2022 तक हर किसी को पक्का मकान देने पर काम युद्ध स्तर चल रहा है। पिछले चार सालों में दो करोड़ मकान बन भी चके हैं। खेती हर मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने के लिए आवंटन में भारी बढ़ोतरी हुई है। पहले के 34 हजार करोड़ रूपए से बढ़कर यह आवंटन सालना 58 हजार करोड़ रूपए हो गया है। सरकार के सामाजिक कार्यों पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ा है। सरकारी काम कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई दे, इसके लिए जियो टैगिंग जैसीं आधुनिक टेक्नोलॉजी मुफीद साबित हुई है। इससे गांव व गरीबों की योजनाओं में सेंध लगाना आसान नहीं रह गया है अब तक 23 राज्यों के 40 लाख पक्के मकानों को जियो टैग कर दिया गया है। जबकि मनरेगा के तहत तकरीबन 3.5 करोड़ निर्मित विकास कार्यों को जियो टैग किया गया है। गरीबी को घरेलू खपत और सुविधाओं के मापदंड़ों के आधार पर आंका जाता है। सरकार ने उन मानकों पर भी काम तेज किया है। सभी घरों में शौचालय और पेयजल की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उज्जवला योजना के तहत गरीबों को घरेलू गैस के कनेक्शन और चूल्हे दिए जा रहे हैं। घर–घर बिजली पहुंचाई जा रही है। सभी गांवों को हर मौसम के लिए पक्की व काली सड़कों से जोड़ा जा रहा है। देश में निर्धनता की प्रमुख समस्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है। देश में बढ़ती जनसंख्या दर जिससे स्वास्थ्य, निरक्षरता खराब सुविधाओं से जुझ रहे ग्रामीण क्षेत्र की दयनीय स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा वित्तीय संसाधनों की कमी उच्च जनसंख्या एवं प्रतिव्यक्ति आय मे कमी से जुझ रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी है। लेकिन बेरोजगारी की दरों में भी बढ़ोत्तरी 2026 तक भारत की जनसंख्या 1.5 बिलियन होने की संभावना है। देश विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। जिस तरह से वृद्वि जनसंख्या में हो रही है ऐसें ही बढ़ती रही तो आने वाले समया में नौकरियों की महामारी फैल जाएगी। तथा कमी अधिक देखने को मिलेगी जिससे गरीबी में भी बढ़ोत्तरी होगी स्वास्थ्य एवं कुपोषण में भी बढ़ोत्तरी होगी । जिससे देश में गरीबी अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। गरीबी भूखमरी एवं बेरोजगारी की समस्या भारत में विकास योजनाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। गरीबों का निम्न स्तर, अशिक्षा, जीवन स्तर की गुणवत्ता का अभाव और मानव संसाधन का विकास की पर्याप्तता होती है। निर्धनता रेखा की अवधारणओं के मुल मानवीय आवश्यकतायें के अन्तर्गत पूरा करने में असमर्थता के

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

अन्तर्गत से जुड़ी हुई है। जैसे बीमारीयों से बचने की क्षमता, पर्याप्त पौष्टिक आहार प्राप्त होना, रहने के लिए उपयुक्त जगह, पहने के लिए उपयूक्त वस्त्र, कुछ न्यूनतम स्तर तक शिक्षित होना एवं आर्थिक–सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना।

गरीबी निवारण कार्यक्रम–

❖ **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) (2005)**

- 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम दिया गया।
- यह योजना 1 अप्रैल 2008 को पूरे राज्य में कर दिया गया, इस योजना का नाम 2 अक्टूबर 2009 महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया।
- इसमें 100 दिनों के रोजगार दिया देने का प्रावधान है।
- 1 जनवरी 2016 को 3.63 करोड़ परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ,

❖ **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013)**

- ग्रामीण आबादी क्षेत्र का 75 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों की आबादी 50 प्रतिशत लोग इस योजना के तहत आतें है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल, गेंहू, मोटे, अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल वितरित किया जाता है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फरवरी 2019 में 81.34 करोड़ व्यक्तियों के इच्छित

❖ **राष्टीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एनआरएलएम):(2011)**

- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम(IRDP) की शुरुआत 1978–79 में की गयी, इस योजना के तहत 2300 विकासखण्डों में यह योजना शुरु किया गयी थी।
- छठवीं पंचवर्षीय (1980–85) में ग्रामीण बेरोजगारी एवं भूख, कुपोषित और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए समय–समय पर योजनायें निरन्तर चलायी गई।
- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) का नाम बदल कर 1 दिसम्बर 1999 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) में विलय कर दिया गया था।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

- इस योजना के अन्तर्गत अनेक रोजगार के अवसर प्राप्त हुए जिनमें मत्स्य पालन, बकरी पालन, सिलाई मशीन एवं अनेक रोजगार के अवसर प्राप्त हुए इस योजनाओं से लाभ एवं हानि दोंनो उठाना पड़ा ।
- इस योजना का नाम 2011 में बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) कर दिया गया।

❖ **इन्दिरा आवास योजनाः(1995)**

- एक करोड़ में 76 लाख लाभार्थियों को आवंटित किये जा चुके है।
- 2017–18 में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है। क्रमशः मध्य प्रदेश, तीसरे पर पंश्चिम बंगाल है।
- इस योजना के तहत आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, महिलायें किसी भी जाति की हो, मध्यम आय वर्ग, कम आय वाले लोग इस योजना के अन्तर्गत आते है।

❖ **प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के उद्देश्य**

- लाभार्थी को 1.2 रू. लाख तक प्रदान किये जाते हैं।
- उत्तर–पूर्व, पहाड़ी क्षेत्रों, इंटीग्रेटेड ऐक्शन प्लान, और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हाउसिंग के लिए 1.3 रू. लाख प्रावधान है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की पहचान सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना से उपलब्ध समंकों के अनुसार की जाएगी ।

❖ **मिशन इन्द्रधनुष अभियानः(2014)**

- इस योजना के अन्तर्गत सात बीमारियों को सम्मिलित किया जैसे–टीकाकरण, पोलियो, टीबी, कालीखासी, खसरा, डिफ्थीरिया एवं हेपेटाइटिस बी।
- इस योजना को सात रंगों से प्रदर्शित करता है।
- सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत सभी बच्चों को टीकाकरण के लिये सुशासन दिवस के अवसर पर प्रारम्भ किया था।

❖ **स्वच्छ भारत अभियानः(2014)**

- इस योजना मुख्य नारा एक कदम स्वच्छता की ओर।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाना।

❖ समस्या का विवरण–

वर्तमान शोध में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के बड़ागांव विकास खण्ड़ के ग्रामीण विकास पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की भूमिका और प्रभाव का अध्ययन किया गया है। वर्तमान में, अनुसंधान के एक सीमित निकाय में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शामिल हैं जो गरीबी की भूमिका और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव पर केंद्रित हैं । हमारे देश के करोड़ों लोग भूखमरी की कगार पर हैं तथा प्रतिदिन हजारों लोगों की मृत्यु, कुपोषण, भूख, तथा जीवन के लिए निम्नतम आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण हो रही है। निर्धनता से तंग आकर आत्महत्या करने अथवा स्वजनों की हत्या करके आत्महत्या करने की बातें समाचार पत्रों में प्रायः पढ़ने को मिलती रहती है। ऐसी परिस्थिति में एक स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु तथा मानवीय मूल्यों के विकास एवं उनकी रक्षा के लिए निर्धनता निवारण का कार्य अत्यन्त आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक जटिल समस्या आज भी बनी हुई, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा होने के पश्चात् भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में असमर्थ है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग जिनकों सरकारी योजनों का लाभ तो प्राप्त तो कर रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत से लोग है, जिन्हें जागरूकता का अभाव, जानकारी का अभाव, समय की बर्बादी, जातिगत समस्या, अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाये जा रहे मनरेगा कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनेक समस्या व्याप्त रहीं, साक्षात्कार के समय उत्तरदाताओं ने मनरेगा की रोजगार एवं आय को कम बताया जिनमें उनके परिवार की खर्च नहीं चल पाता है। मनरेगा के तहत उनको समय समय पर कार्य नहीं प्राप्त हो पाता है, जिसकी वजह से इस योजनाओं के तहत वे बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हैं, इसका हल ढूढने के लिए शोध विषयः वाराणसी जनपद के बड़ागाँव विकास खण्ड में गरीबी निवारण कार्यक्रमों का चुनाव किया गया।

❖ महत्व और अनुसंधान का औचित्य–

यह अध्ययन ग्रामीण समुदाय के गरीबी निवारण कार्यक्रमों के स्रोतों से सम्बन्धित समस्याओं एवं चुनौती, व कल्याणकारी योजनाओं के प्रकृति पर पूर्णरुप से आधारित है, चूँकि एक समृद्धि राष्ट्र का विकास तभी सम्भव है, जब उस राष्ट्र से गरीबी जैसे भयंकर समस्या का पतन हो सके है। शोध विषय का महत्व ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण गृह पात्रता से सम्बन्धी कार्यक्रमों के विषय में लोगों में जागृति व चेतना उत्पन्न करना ताकि वे एक स्वास्थ्यप्रद व सुरक्षित मानवपूँजी का निर्माण हो सके, जो न सिर्फ परिवार के

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

आर्थिक विकास में सहायक है, बल्कि एक समाज व राष्ट्र के मजबूत आर्थिक विकास, के लिए भी अतिमहत्वपूर्ण रहा।**''वाराणसी जनपद के बड़ागाँव विकास खण्ड में गरीबी निवारण कार्यक्रमों का अध्ययन''** उपयोगिता उत्तर प्रदेश के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की स्थिति का अध्ययन करने में सहायक हुई है । यह शोध कार्य गृह पात्रता परिवारों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों परियोजनाओं तथा सरकारी, गैर सरकारी संगठनों के लिए यथासम्भव, मार्गदर्शन इसके माध्यम से सहज किया गया। इस प्रकार यह अध्ययन विषय स्वयं में विशिष्ट महत्व रखता है। यह शोध नीति निर्माताओं को उन विनियमों को विकसित करने में सहायता करेगा जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के बड़ागांव ब्लॉक के ग्रामीण लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और प्रगतिशील नीतियों के प्रावधान को बढ़ावा देते हैं ।

❖ साहित्य समीक्षा–

पाल,राजेश.(2011): के तहत ढांचागत परिवर्तन, शैक्षिक विकास, जागरूकता में वृद्धि, दृष्टिकोण में परिवर्तन, प्रेरणा और दृष्टिकोण परिवर्तन के बिना गरीब तब के की आर्थिक बेहतरी हासिल नहीं की जा सकती ।

विश्व बैंक.(2015): के तहत गरीबी एक बहुआयामी घटना है, गरीबी के स्तर को अक्सर आय और खपत के आधार पर आर्थिक आयामों का उपयोग कर मापा जाता है

भगवती जे,एवं पनगढिया.(2013): के अन्तर्गत आर्थिक विकास गरीबी उन्मूलन के लिए प्रमुख साधनों में से एक है और उत्पादक रोजगार के माध्यम से गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त हो।

सेन ए.के.(2000):ने गरीबी के कारणों के रूप में सामाजिक बहिष्कार और क्षमता अभाव का हवाला देते हैं।

अब्रामों(2015): गरीबी में रहने वाले लोगों को सभ्य काम की उच्च घाटे है।

योगेमा, एस एवं चिलेश, एन एम टी(2016): कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम महत्वपूर्ण निवेश के बावजूद खराब प्रदर्शन जारी ।

अहमद,ई जहान, एन फतिमा, तुज, जोहरा(2014): समाजिक बीमा योजनाओं और सामाजिक सहायता भुगतान सहित सामाजिक सुरक्षा पर कई सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम और सार्वजनिक खर्च, दुनिया भर के कई विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के औजार के रूप में कार्यक्रम जारी रखते हैं

❖ 3. अनुसन्धान पद्धति

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

"वाराणसी जनपद के बड़ागॉव विकास खण्ड में रहने वाले उत्तरदाताओं से जनसांख्यिकी विशेषताओं और आर्थिक सामाजिक परिवेश पर उनकी प्रतिक्रिया को चिन्हित करने के लिए अनुसन्धानकर्ता उनसे प्रश्न के उत्तर को पुछकर अनुसूॅची को चिन्हित किया गया था। उत्तरदाताओं से प्रश्न के पहले दो खण्डों के लिए बन्द एवं खुले प्रश्नों को चिन्हित किये गये और वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। उत्तरदाताओं से गरीबी के कारणों के बारे मैं पंच बिंदु समान मापनी (five point likert scale) पर आधारित प्रश्न पूछ गये थे जिन के पांच विकल्प थे, **दृढता से सहमत (5), सहमत (4), अनिश्चित (न तो सहमत हैं और न ही असहमत) (3), असहमत (2), दृढ़ता से असहमत (1)।**

उत्तरदाताओं से सरकारी कार्यक्रमों से प्राप्त लाभ पर अपनी सन्तुष्टि को प्रकट करने को कहा गया था जिन्हें अनुसन्धानकर्ता ने उनके उत्तर को पुछकर प्रश्नों के उत्तर को अनंसन्धानकर्ता पांच विकल्प चिन्हित किया । **पूर्णतया संतुष्ट (5), संतुष्ट (4), औसत (3),असंतुष्ट (2),पूर्णतया असंतुष्ट (1)**

- **अध्ययन क्षेत्र**

उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240928 वर्ग किमी0 में स्थित है, जिसकी उत्तरी अक्षांश 23^{0} 52^{I} व 30^{0} 24^{I} उत्तरी अक्षांश तक 77^{0} 05^{I} से 84^{0} 38^{I} पूर्वी देशान्तर तक स्थित है। जो कि भारत के क्षेत्रफल से 7.33 प्रतिशत वर्ग तक स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है। उत्तरप्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार 19.98 करोड़ है। वाराणसी के भौगोलिक क्षेत्रफल 1535 वर्ग किमी0 पर स्थित है। इसका देशान्तर 83^{0}0^{0} अक्षांश 25^{0}20^{1} है। 2011 के आंकडे के अनुसार वाराणसी की कुल जनसंख्या 36.76 लाख जिनमें पुरूषों की कुल जनसंख्या 19.21 लाख एवं स्त्रियों की कुल जनसख्या 17.54 लाख है। शोध का चयन एक ब्लाक में से 20 ग्राम पंचायतों का सोद्देश्य नमूनाकरण तकनीक **(Purposive Sample-Non Random Sampling Technique)**के आधार पर चयन किया गया है, इनमें से वर्ष 2015–18 के आंकड़े को एकत्रित किया गया है। जिनमें शोध सर्वेक्षण क्रमश खरावन, कठिरांव, अनेई, असवारी, तिलवार, चंगवार, धनजयपुर, रघुनाथपुर, रायपुर, मझगवां, चिलबिला, बलुआ, बौलिया, बर्जी, कनियर, , लखीमपुर, सोनपुरवां, महिमापुर, कुसुमुरा, बरही नेवादा. है।

- **प्रतिदर्श की इकाई–** बड़ागाँव विकास खण्ड़ प्रतिदर्श की एक इकाई के रूप में चयन किया गया है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

- **प्रतिदर्श का चयन–**अनुसन्धानकर्ता ने अनुसन्धान क्षेत्रों का चयन सोद्देश्य नमूनाकरण तकनीक **(Purposive Sample- Non Random Sampling Technique)** के आधार पर न्यादर्श का चयन किया है।

- **न्यादर्श का आकार–** न्यादर्श का आकार 20 ग्रामपंचायतों में से हर एक ग्राम पंचायतों में से 20 परिवारों का सोद्देश्य नमूनाकरण तकनीक के आधार पर चयन किया जिनमें 20 ग्रामपंचायतों में से 400 परिवारों का चयन सोद्देश्य नमूनाकरण तकनीक**(Purposive Sample- Non Random Sampling Technique)** के आधार पर किया गया है।

- अनुसंधान उद्देश्य के लिए जानकारी / डेटा एकत्र करने के लिए शोधकर्ता ने सोद्देश्य नमूनाकरण तकनीक **(Purposive Sample- Non Random Sampling Technique)** का उपयोग किया। वाराणसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़ॉगांव ब्लॉक से आंकड़े एकत्र किए गए थे। बड़ागांव ब्लॉक में कुल 86 ग्राम पंचायतें थीं। 86 ग्राम पंचायतों में से 20 ग्राम पंचायतों का चयन सोद्देश्य नमूनाकरण तकनीक **(Purposive Sample- Non Random Sampling Technique)** नमूना तकनीकों के माध्यम से किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत से, 20 उत्तरदाताओं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को गैर यादृच्छिक नमूना तकनीक ढंग से चुना गया था। वाराणसी जिले के बड़गांव ब्लॉक के निम्नलिखित 20 ग्राम पंचायतों से आंकड़े एकत्र किए गए थे।

❖ **प्राथमिक आँकडों –**

प्राथमिक आँकड़ों का संकलन नये सिरे से किया गया तथा साक्षात्कार अनुसूची से तात्पर्य अध्ययन की समस्या से सम्बन्धित प्रश्नों की सूँची से बनाया गया, जिनके द्वारा अनुसंधानकर्ता, अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचनादाता या उत्तरदाता के सम्मुख बैठकर उससे सरकार द्वारा चलाये जा रहे, गरीबी निवारण कार्यक्रमों के तहत निहित प्रश्नों को पूछकर अपने हाथों से प्रत्येक अनुसूँची को भरा गया है।

❖ **द्वितीयक आँकडों –**

द्वितीय आँकड़ों का संग्रहण आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण, संगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, योजना आयोग (नीति आयोग) रिपोर्ट, विश्व बैंक, एच0डी0आई0, यू0एन0डी0पी0,

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

यू0एन0ओ0, एम0पी0आई0 पुस्तकालय, पी0सी0ए0, उत्तर प्रदेश योजना आयोग से लिया गया, तथा सन्दर्भ ग्रन्थों में पुस्तकों, शोध ग्रन्थों शोध पत्रो एवं जनगणना 2011, सरकारी रिपोर्ट एवं सरकारी प्रकाशन से संकलित किया गया है।

❖ **ग्राम पंचायतों की सूची–**

3.26.तालिका– नमूना आकार विवरण कुल ग्रामपंचायत उत्तरदाताओं की संख्या

क्र0स0	जनपद	इकाई ब्लॉक	कुल ग्रामपंचायत	ग्रामपंचायत	उत्तरदाताओंकी संख्या
1				कठिराँव	20
2				खरावन	20
3				चिलबिला	20
4				सोनपुरवाँ	20
5				लखीमपुर	20
6				कनियर	20
7				असवारी	20
8				मझगवाँ	20
9				कुसुमुरा	20
10	वाराणसी	बड़ागाँव	86	रघुनाथपुर	20
11				बौलिया	20
12				बलुआ	20
13				बरहीनेवादा	20
14				बर्जी	20
15				महिमापुर	20
16				धंनजयपुर	20
17				चंगवार	20
18				अनेई	20
19				रायपुर	20
20				तिलवार	20
कुल नमूना					400

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

कारक विश्लेषण का प्रयोग गरीबी के सबसे महत्वपूर्ण कारणों तथ्यों की पहचान करने के लिए किया गया था।

तालिका–4.44 केएमओ और बार्टलंट्स टेस्ट

केएमओ और बार्टलंट्स टेस्ट **KMO and Bartlett's Test**		
प्रतिचयन पर्याप्तता का केएमओ माप Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.782
Bartlett's Test of Sphericity बार्टलेट के परीक्षण के नमूने	Approx. Chi-Square	3973.675
	df	55
	महत्वपूर्ण Sig.	.000

आंकड़ों की पर्याप्तता का परीक्षण कैसर–मेयर–ओल्किन (केएमओ) के परिणामों के आधार पर किया जाता है, जो उपरोक्त तालिका में प्रदान की गई गोलाई की पर्याप्तता और बार्टलेट के परीक्षण के नमूने Bartlett's test of sphericity (homogeneity of Variance) के आधार पर किया जाता है। प्रतिचयन पर्याप्तता का केएमओ माप 0.782 है जो यह इंगित करता है कि वर्तमान आंकड़े कारक विश्लेषण के लिए उपयुक्त हैं। इसी प्रकार, गोलाई का बार्टलेट का परीक्षण महत्वपूर्ण (significant ($p < 0\text{-}001$) है, जो विश्लेषण के साथ आगे बढ़ने के लिए चरों के बीच पर्याप्त सहसंबंध के अस्तित्व की व्याख्या करता है।

तालिका–4.45 संचयी Communalities

संचयी **Communalities**		
	Initial	Extraction
परिवार में सदस्यों का अधिक होना	1.000	.807
वित्त की समस्या	1.000	.854
घर में कोई शिक्षित न होना	1.000	.826
स्वयं का अशिक्षित होना	1.000	.321

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

बेरोजगारी	1.000	.854
छोटी उम्र में मजदूरी करना	1.000	.759
पितृ सम्पत्ति का होना	1.000	.720
दुसरों के जमीनों में मजदूरी करना	1.000	.821
अस्वस्थता	1.000	.839
अत्यधिक ऋण होना	1.000	.747
सरकारी योजनाओं की जागरुकता का अभाव	1.000	.931
Extraction Method: Principal Component Analysis.		

तालिका–**4.46** कुल भिन्न व्याख्या

Total Variance Explained									
	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
Component	Total	प्रतिशत of Variance	Cumulative प्रतिशत	Total	प्रतिशत of Variance	Cumulative प्रतिशत	Total	प्रतिशत of Variance	Cumulative प्रतिशत
1	**5.795**	**52.686**	52.686	5.795	52.686	52.686	5.363	48.751	48.751
2	**1.426**	**12.962**	65.648	1.426	12.962	65.648	1.636	14.871	63.622
3	**1.257**	**11.428**	**77.076**	1.257	11.428	77.076	1.480	13.454	77.076
4	.943	8.569	85.645						
5	.490	4.457	90.102						
6	.429	3.902	94.004						
7	.238	2.166	96.170						
8	.166	1.510	97.680						
9	.124	1.129	98.809						
10	.076	.695	99.504						
11	.055	.496	100.000						
Extraction Method: Principal Component Analysis.									

व्याख्या

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

ऊपर तालिका में, उत्पादन निष्कर्षण के बाद और रोटेशन के बाद, निष्कर्षण से पहले प्रत्येक रैखिक घटक (कारक) के साथ जुड़े (Eigen) मूल्यों को सूचीबद्ध करता है। निष्कर्षण से पहले, आउटपुट डेटा सेट के भीतर 11 रैखिक घटकों की पहचान की है। निष्कर्षण और रोटेशन के बाद, सबसे महत्वपूर्ण कारक 1 कुल विचरण के 52.686 प्रतिशत समझाया, कारक 2 कुल विचरण के 12.962 प्रतिशत और कारक 3 कुल विचरण की व्याख्या की 11.428 प्रतिशत कुल विचरण के बारे में बताया. जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, यह पाया गया कि कुल 11 घटकों (गरीबी के सबसे महत्वपूर्ण कारणों) से, पहला कारक सबसे महत्वपूर्ण है और निकाला जा सकता है।

4.1 चित्र– स्क्री प्लाट

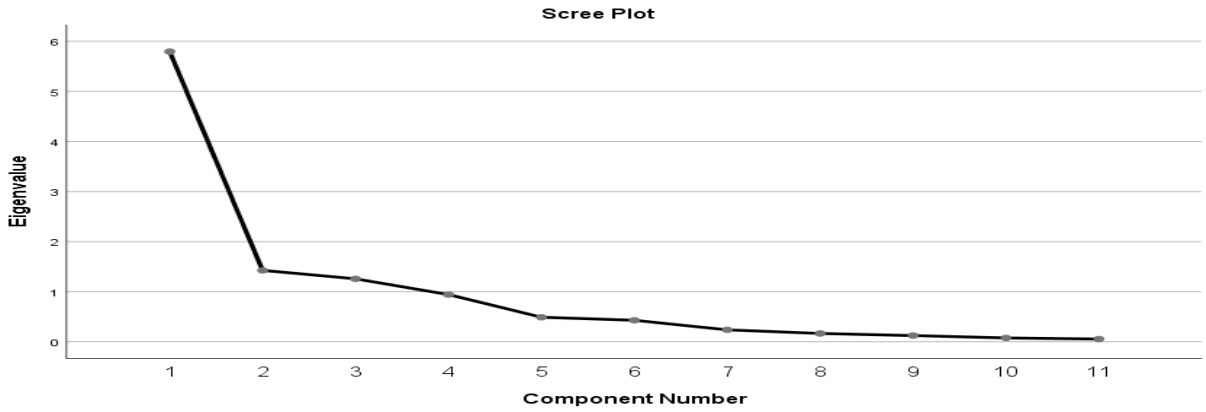

तालिका–4.47 घटक आब्यूह

घटक आब्यूह (Component Matrix[a])			
	घटक (Component)		
	1	2	3
वित्त की समस्या	.920	-.080	-.023
अस्वस्थता	.891	.209	.019
सरकारी योजनाओं की जागरुकता का अभाव	.865	.172	-.392
दुसरों की जमीनों में मजदूरी करना	.852	-.281	.132
छोटी उम्र में मजदूरी करना	.850	-.051	-.185

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

परिवार में सदस्यों का अधिक होना	.772	-.456	.048
पित्तृ सम्पत्ति का न होना	.768	.226	.280
अत्यधिक ऋण का होना	.755	.364	-.209
घर में कोई शिक्षित न होना	.207	.736	.491
स्वयं का अशिक्षित होना	.303	-.474	-.066
बेरोजगारी	.256	-.326	.826
Extraction Method: Principal Component Analysis.			
a. 3 components extracted.			

तालिका–4.48 घुमाए गए घटक आव्यूह

घुमाए गए घटक आव्यूह **Rotated Component Matrix**[a]			
	घटक (Component)		
	1	2	3
सरकारी योजनाओं की जागरुकता का अभाव	**.944**	-.167	.112
अस्वस्थता	**.891**	.197	-.078
वित्त की समस्या	**.861**	.266	.206
अत्यधिक ऋण का होना	**.845**	-.098	-.149
छोटी उम्र में मजदूरी करना	**.835**	.091	.233
पित्तृ सम्पत्ति का न होना	**.723**	.390	-.211
दुसरों की जमीनों में मजदूरी करना	**.717**	.453	.320
परिवार में सदस्यों का अधिक होना	**.619**	.415	.502
बेरोजगारी	-.006	**.924**	.012
घर में कोई शिक्षित न होना	.263	.249	**-.834**
स्वयं का अशिक्षित होना	.193	.188	**.499**
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.			
a. Rotation converged in 6 iterations.			

जाँच – परिणाम प्रतिशत गरीबी के सबसे महत्वपूर्ण कारण

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

वर्तमान अध्ययन कारक विश्लेषण में विवरण (चर) के लिए घूर्णनित कारक लोडिंग, गरीबी के सबसे महत्वपूर्ण कारण दर्शाती है

रोटेटेड घटक मैट्रिक्स की तालिका को देखते हुए, हम निष्कर्ष निकाला–

फैक्टर –1 निम्नलिखित 8 चर शामिल हैं

1. सरकारी योजनाओं की जागरूकता का अभाव
2. अस्वस्थता
3. वित्त की समस्या
4. अत्यधिक ऋण होना
5. छोटी उम्र में मजदूरी करना
6. पैतृक संपत्ति का न होना
7. दुसरों के जमीनों में मजदूरी करना
8. परिवार में सदस्यों का अधिक होना

फैक्टर –2 निम्नलिखित 1 चर शामिल हैं

1. बेरोजगारी

फैक्टर –3 निम्नलिखित 2 चर शामिल हैं

1. घर में कोई शिक्षित न होना
2. स्वयं का अशिक्षित होना

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

तालिका–**4.49** घुमाए गए घटक परिवर्तन आव्यूह

घटक परिवर्तन आब्यूह (**Component Transformation Matrix**)			
घटक (Component)	1	2	3
1	.950	.281	.135
2	.230	-.340	-.912
3	-.211	.897	-.388
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.			

आवृत्ति विश्लेषण प्रतिशत सरकारी कार्यक्रमों से प्राप्त लाभ पर उत्तरदाताओं की सन्तुष्टि

तालिका 4.61 मनरेगा

मनरेगा				
	आवृत्ति **Frequency**	प्रतिशत **Percent**	वैधता प्रतिशत **Valid Percent**	संचयी प्रतिशत **Cumulative Percent**
सन्तुष्ट	70	17.5	17.5	17.5
औसत	34	8.5	8.5	26.0
असन्तुष्ट	138	34.5	34.5	60.5
पुर्णतया असन्तुष्ट	158	39.5	39.5	100.0
कुल	400	100.0	100.0	

व्याख्या

उपरोक्त आवृत्ति तालिका से, यह देखा जा सकता है कि कुल 400 उत्तरदाताओं में से, मनरेगा योजना से 17.5 प्रतिशत संतुष्ट, 8.5 प्रतिशत, औसत, 34.5 प्रतिशत असंतुष्ट और 39.5 प्रतिशत पूर्णतया असंतुष्ट है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

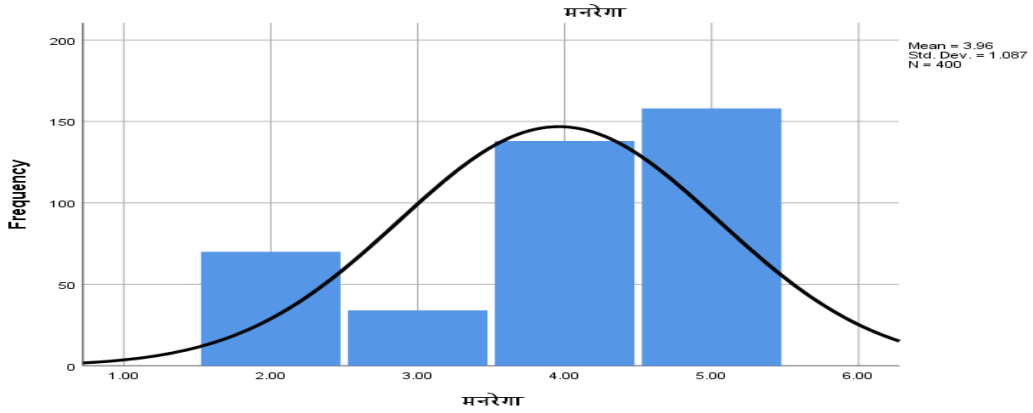

तालिका 4.62 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)				
	आवृत्ति **Frequency**	प्रतिशत **Percent**	वैधता प्रतिशत **Valid Percent**	संचयी प्रतिशत **Cumulative Percent**
पूर्णतया सन्तुष्ट	26	6.5	6.5	6.5
सन्तुष्ट	57	14.2	14.2	20.8
औसत	52	13.0	13.0	33.8
असन्तुष्ट	125	31.3	31.3	65.0
पुर्णतया असन्तुष्ट	140	35.0	35.0	100.0
कुल	400	100.0	100.0	

व्याख्या

उपरोक्त आवृत्ति तालिका से, यह देखा जा सकता है कि कुल 400 उत्तरदाताओं में से, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से 6.5 प्रतिशत पूर्णतया संतुष्ट, 14.2 प्रतिशत संतुष्ट, 13.0 प्रतिशत, औसत, 31.3 प्रतिशत असंतुष्ट और 35.0 प्रतिशत पूर्णतया असंतुष्ट है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

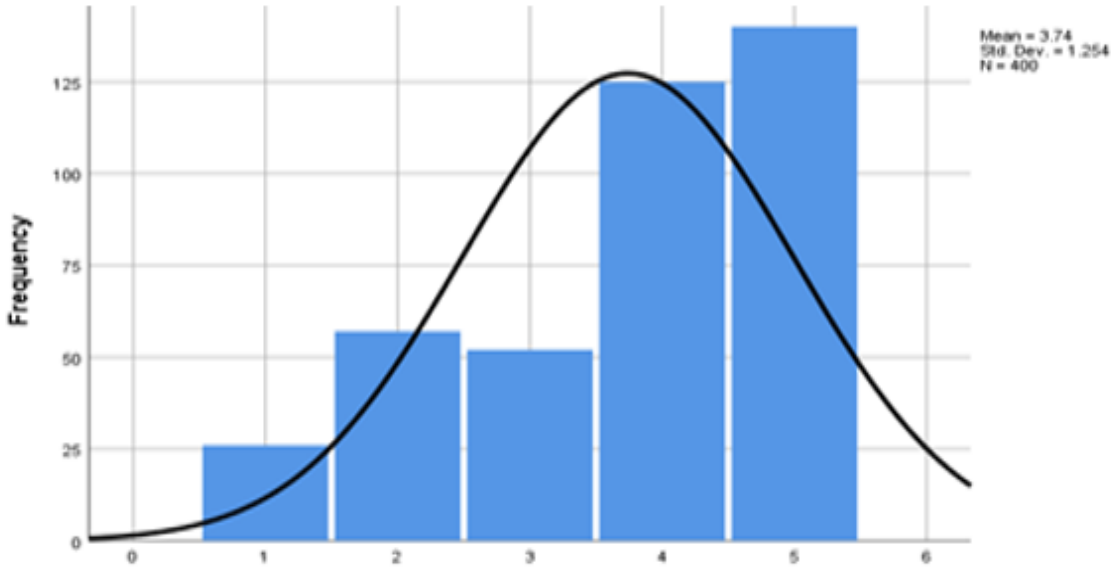

तालिका–**4.63** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) एनएफएसए(

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) एनएफएसए(				
	आवृत्ति **Frequency**	प्रतिशत **Percent**	वैधता प्रतिशत **Valid Percent**	संचयी प्रतिशत **Cumulative Percent**
पूर्णतया सन्तुष्ट	30	7.5	7.5	7.5
सन्तुष्ट	39	9.8	9.8	17.3
औसत	18	4.5	4.5	21.8
असन्तुष्ट	221	55.2	55.2	77.0
पुर्णतया असन्तुष्ट	92	23.0	23.0	100.0
कुल	400	100.0	100.0	

व्याख्या

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

उपरोक्त आवृत्ति तालिका से, यह देखा जा सकता है कि कुल 400 उत्तरदाताओं में से, राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए) से 7.5 प्रतिशत पूर्णतया संतुष्ट, 9.8 प्रतिशत, संतुष्ट, 4.5 प्रतिशत औसत, 55.2 प्रतिशत असंतुष्ट और 23.0 प्रतिशत पूर्णतया असंतुष्ट है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आनियम (NFSA)

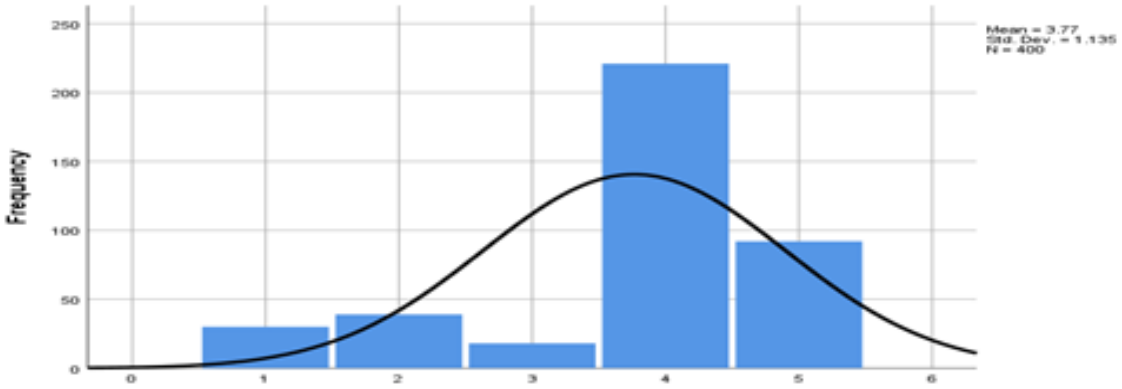

तालिका–4.64 इन्दिरा आवास योजना**(IAY)**

इन्दिरा आवास योजना**(IAY)**				
	आवृत्ति **Frequency**	प्रतिशत **Percent**	वैधता प्रतिशत **Valid Percent**	संचयी प्रतिशत **Cumulative Percent**
पूर्णतया सन्तुष्ट	63	15.8	15.8	15.8
सन्तुष्ट	261	65.2	65.2	81.0
औसत	26	6.5	6.5	87.5
असन्तुष्ट	48	12.0	12.0	99.5
पुर्णतया असन्तुष्ट	2	.5	.5	100.0
कुल	400	100.0	100.0	

व्याख्या

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

उपरोक्त आवृत्ति तालिका से, यह देखा जा सकता है कि कुल 400 उत्तरदाताओं में से, इन्दिरा आवास योजना से 15.8 प्रतिशत पूर्णतया संतुष्ट, 65.2 प्रतिशत संतुष्ट, 6.5 प्रतिशत औसत, 12.0 प्रतिशत असंतुष्ट और 0.5 प्रतिशत पूर्णतया असंतुष्ट है।

इन्दिरा आवास योजना(IAY)

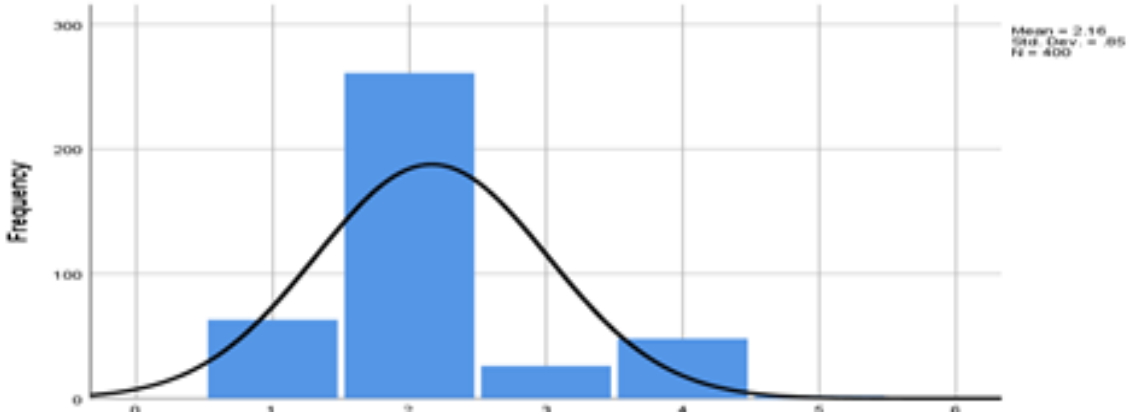

सुझाव एवं चर्चा–

बड़ागांव विकास खण्ड़ के ग्रामपंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पौष्टिक आहार एवं ग्रामीण सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव बना हुआ है, पीने का पानी एवं बिजली भी सीमित हैं । गरीबी एक दुष्चक्र और अभिशाप है जो गरीब को गरीबी से बाहर नही आने देता है । गरीबी के अनेक कारण हो सकते हैं । इस अध्ययन से पता चलता है के छोटी उम्र में मजदूरी करना, दुसरों कि जमीनों में मजदूरी करना, अत्यधिक ऋण होना और सरकारी योजनाओं की जागरूकता का अभाव गरीबी के मुख्य कारण हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की संरचना की जड़ें बहुत गहरी हैं इसी कारण गरीबी को कम करने और गरीबी के दुष्प्रभाव से छुट कारा पाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर गरीबी निवारण कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है । निर्धनता की परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा कई योजना और रणरीतियाँ बनायीं जाती है जिसमे से मनरेगा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और इन्दिरा आवास योजना निर्धनता को कम करने की लिए

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

बहुत महत्वपूर्ण योजना, हैं । मनरेगा योजना के लाभ से अधिकांश लोगों ने असन्तुष्ट पर चिह्न किये थे । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना चयनित परिवारों ने लाभों से अधिकांश लोगों ने असन्तुष्ट पर चिह्न किये थे, कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना से लाभ 'नहीं' होता है राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए).ये योजना भी गरीबी निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता के स्तर को कम करने क प्रयास में लगी हुई है लेकिन फिर भी चयनित परिवार लाभों से असन्तुष्ट है। लाभार्थियों के अनुसार इस योजना से प्रति सदस्यों के हिसाब से 5 किग्रा अनाज प्राप्त होता जिससे घर के लोगों का उपभोग करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे असन्तुष्ट है। इन्दिरा आवास योजना दिल चस्पबात यह है कि हमारे अध्ययन के परिणामों से पता चला है कि लोग सरकार के इस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से अधिक संतुष्ट थे ।

REFERENCES

- Abramo, L. (2015), Uma década de promoçãodotrabalhodecente no Brasil: umastratégia de açãobaseada no diálogo social, Brasilia, International Labour Organization (ILO).
- Ahmed I, Jahan N, Fatema-Tuz-Zohora (2014) Social safety net programme as a mean to alleviate poverty in Bangladesh. Developing Country Studies.;4(17): 46–54. ISSN (Online):2225–0565.
- Dr. Rajesh Pal, (2011) Assistant Professor, Department of Economics, Mahatma Gandhi KashiVidyapith Varanasi (India)- Poverty Alleviation in India: Programmes, Challenges and Strategy
- Growth Ambarkhane D. and poverty reduction as complimentary processes an approach to inclusive growth. Journal of Commerce & Management Thought. 2013;4(4):904–921. ISSN (Online):0976-478X.
- Sen AK. Poverty: an ordinal approach to measurement. Econometrica. 1976;44(2):219–231.
- World Bank. The World Bank: Annual Report 2015. The World Bank, Washington, DC, USA. 2015.

- Yalegama S, Chileshe N, Ma T. Critical success factors for community-driven development projects: A Sri Lankan community perspective. International Journal of Project Management. 2016;34:643–659.
- Ghose, Ajit. (2015): *Addressing the employment challenge: India's MGNREGA*. No. id: 7469. 2015.
- Ministry of rural Development, Government ofindia.(2014).Mahatma Gandhi national rural employment guarantee act. http//nrega.nic.in//metnrega/write readdata/circulars/prc-2014.VERSION-4 FINAL.PDF.CONSULTED On 25August 2015.
- Ministry of rural Development, Management Information system.(2012)
- Shankar,Kripa.(2004):"How efficient is TPDS in Tribal areas?." *Economic and Political Weekly* (2004): 2093-2096.

- ओझा, बी0 एल0 ओझा, अग्रवाल, अनुपम (2009–10): अर्थ''ाास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था, महात्मा गाँधी का''ी विद्यापीठ, वाराणसी पे0 न0 420–421